प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

24.04.2026 / प्रादेशिक समाचार / 1800 बजे

पश्चिम एशिया ब्रीफिंग

केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एल.पी.जी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और किसी भी वितरक के यहां आपूर्ति की कमी नहीं हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर–मंत्रालयी ब्रीफिंग में केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति 70 प्रतिशत तक बहाल हो चुकी है और इस महीने अब तक एक लाख 47 हजार से अधिक एलपीजी सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कल पांच किलो के 81 हजार से अधिक एलपीजी सिलेन्डर बेचे गये। सुजाता शर्मा ने बताया कि लगभग पांच लाख 27 हजार पी.एन.जी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने को वचनबद्ध है और सभी अस्पतालों में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने आज शिमला में कहा कि केंद्र सरकार ने मातृ–शिशु अस्पताल अलग बनाने और हिमाचल में भी इसकी शुरूआत की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला के कमला नेहरू अस्पताल से स्त्री रोग विभाग को आई.जी.एम.सी. शिमला में स्थानांतरित करने से महिलाओं को रोबोटिक तकनीक से अच्छा ईलाज मिलेगा। उन्होंने इसे लेकर कुछ संगठनों और डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को गलत बताया।

पंचायती राज दिवस

देश में आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। यह 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन का प्रतीक है, जो 1993 में लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायतीराज दिवस के अवसर पर देशभर के जनप्रतिनिधियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट.............

सिकंदर कुमार

राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने राज्य सरकार पर अपने फैसलों से पलटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बार–बार फैसलों को बदलना मुख्यमंत्री की राजनीति व प्रशासन पर कमज़ोर पकड़ को दर्शाता है। सिकंदर कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने एक सौ 25 यूनिट मुफ़्त बिजली की सुविधा चुनिंदा वर्गों के लिए बंद करने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में इसे वापिस लेना पड़ा। इसी प्रकार प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के वेतन से कटौती के निर्णय को भी सरकार ने वापिस लिया है। सांसद ने कहा कि इससे लोगों के बीच में ये संदेश जा रहा है कि सचिवालय में बैठे अधिकारी व सलाहकार मुख्यमंत्री को सही फीडबैक नहीं दे रहे हैं।

शहरी निकाय

प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए 17 मई को मतदान होगा। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और मतदान को लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नगर परिषद नाहन में लगभग 20 हज़ार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उम्मीदवार 29 व 30 अप्रैल और 2 मई को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नाहन के एस.डी.एम. राजीव सांख्यान ने बताया कि शहर में 18 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

....